नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 127
दि. 09.02.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

एक वर्ष की सरकार, विश्वास की जीत और शालीमार बाग के बदलते सपनों की कहानी

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वर्ष पूरे होने का अवसर केवल एक औपचारिक सालगिरह नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास, प्रशासनिक जिम्मेदारी और जनता की अपेक्षाओं का आईना बनकर सामने आया। शालीमार बाग के पीतमपुरा स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भावुक होना इस बात का संकेत था कि सत्ता का यह एक साल उनके लिए केवल आंकड़ों और फाइलों का नहीं, बल्कि जीवन, संघर्ष और स्मृतियों से जुड़ा सफर रहा है। मंच से बोलते हुए जब उन्होंने अपने बचपन, त्रिनगर से पीतमपुरा तक के सफर और जनता के साथ अपने रिश्ते को याद किया, तो माहौल केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय भी हो गया।

रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में यह साफ किया कि मुख्यमंत्री का पद उनके लिए कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र ने उन्हें पहचान दी, जहां उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती साल बिताए, उसी क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। यह भावनात्मक जुड़ाव उनके शब्दों में साफ झलक रहा था, जब उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके राजनीतिक जीवन में उतार-चढ़ाव आए, चुनावी हार भी झेलनी पड़ी, लेकिन जनता से उनका रिश्ता कभी कमजोर नहीं हुआ।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि लगभग 250 करोड़ रुपये के विकास कार्य या तो पूरे हो चुके हैं या तेजी से प्रगति पर हैं। इन कार्यों में डिस्ट्रिक्ट पार्क का पुनर्विकास, नए प्रवेश द्वार, आकर्षक फाउंटेन, आधुनिक शौचालय, बेहतर फुटपाथ और नागरिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि ये परियोजनाएं केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि क्षेत्र की गरिमा, सुरक्षा और नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों से सीधे जुड़ी हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक साल में विकास की दिशा बदलना आसान नहीं होता, लेकिन नीयत साफ हो और नीति स्पष्ट हो, तो बदलाव दिखने लगता है। उन्होंने वर्ष 2025 में 27 वर्षों बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जनता की उन उम्मीदों की जीत है, जो लंबे समय से अधूरी थीं। उनके अनुसार, दिल्ली की जनता ने विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जनादेश दिया था, जिसे पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।

अपने भाषण में रेखा गुप्ता ने भविष्य की बड़ी योजनाओं का भी खाका खींचा। उन्होंने मुनक नहर पर प्रस्तावित लगभग 5000 करोड़ रुपये की एलिवेटेड रोड परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह दिल्ली के ट्रैफिक दबाव को कम करने और आवागमन को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही नहर के किनारे सौंदर्यीकरण, छठ घाटों का विकास और हरित क्षेत्रों के विस्तार की योजना को उन्होंने पर्यावरण और आस्था के संतुलन का उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री ने आधुनिक ऑडिटोरियम, मॉडल स्कूल, कम्युनिटी हॉल, आयुर्वेदिक अस्पताल के विस्तार, उन्नत जच्चा-बच्चा केंद्र और नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं केवल वर्तमान की जरूरतें नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। उनके अनुसार, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में निवेश ही किसी शहर को लंबे समय तक मजबूत बनाता है। उन्होंने सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट, पार्कों और बाजारों के व्यापक सुधार को 'हर घर तक पहुंचता विकास' बताया।

रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में दिल्ली के समग्र विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बेहतर समन्वय से राजधानी के बुनियादी ढांचे को नई गति मिली है। उन्होंने फ्लाईओवर, सड़कों के विस्तार, मेट्रो नेटवर्क के विकास और इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली तेजी से आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल शहर की ओर बढ़ रही है। उनके अनुसार, यह बदलाव केवल कागजों में नहीं, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन में महसूस किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक साल में सरकार ने केवल योजनाएं शुरू नहीं कीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति को बदलने की कोशिश की है। पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही को उन्होंने शासन का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि सरकार उनके टैक्स और संसाधनों का सही उपयोग कर रही है। इसी भरोसे के बल पर सरकार आगे के वर्षों में और बड़े फैसले लेने की हिम्मत जुटा सकती है।

कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के भाषण को ध्यान से सुना। कई लोगों के लिए यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में हो रहे बदलावों को देखने और समझने का अवसर था। पार्क के पुनर्विकास और नई सुविधाओं को देखकर लोगों में उत्साह साफ दिख रहा था। यह माहौल इस बात का संकेत था कि विकास कार्यों का असर जमीन पर महसूस होने लगा है।

रेखा गुप्ता ने अपने भाषण के अंत में यह भी कहा कि सरकार की असली परीक्षा अभी बाकी है। एक साल केवल शुरुआत है, असली चुनौती आने वाले वर्षों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार दिल्ली को न केवल एक बेहतर राजधानी बनाएगी, बल्कि एक ऐसा शहर भी बनाएगी, जहां हर वर्ग को सम्मान, अवसर और सुरक्षा मिले। उन्होंने कहा कि सत्ता का यह सफर उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। दिल्ली में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम इसलिए भी खास रहा, क्योंकि इसमें भावनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का अनोखा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री का भावुक होना यह दर्शाता है कि राजनीति के कठोर माहौल में भी मानवीय संवेदनाएं जीवित हैं। शालीमार बाग से पेश किया गया यह रिपोर्ट कार्ड केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि उस भरोसे की कहानी है, जो जनता और सरकार के बीच धीरे-धीरे मजबूत हो रही है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये वादे और योजनाएं किस हद तक दिल्ली के चेहरे को बदल पाती हैं, लेकिन इतना तय है कि एक साल की इस यात्रा ने राजधानी की राजनीति और विकास की दिशा में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है।

पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोपों से असम की राजनीति में उबाल, गोगोई परिवार पर जांच की मांग तेज

असम की राजनीति इन दिनों एक बड़े राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवाद की गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों ने राज्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सियासी हलचल पैदा कर दी है। 'पाकिस्तानी कनेक्शन' जैसे संवेदनशील आरोप सामने आने के बाद असम में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट के आधार पर अब असम कैबिनेट ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग केंद्र सरकार से की है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि असम के एक बड़े राजनीतिक नेता का पाकिस्तान से सीधा संपर्क रहा है और यह मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बिना लाग-लपेट के कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब उनके पिता तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री थे, तब गौरव गोगोई पाकिस्तान गए थे। मुख्यमंत्री के अनुसार इस यात्रा की जानकारी न तो राज्य पुलिस को दी गई थी और न ही केंद्र सरकार को, जो कि अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती है।

सीएम सरमा ने यह भी आरोप लगाया कि गौरव गोगोई ने पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास का दौरा किया था, जिसे उन्होंने एक असामान्य और संदिग्ध गतिविधि बताया। उनका कहना था कि किसी भी जिम्मेदार भारतीय राजनेता का इस तरह से पाकिस्तान जाना और वहां की गतिविधियों में शामिल होना जांच के दायरे में आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि SIT की रिपोर्ट में इस पूरे मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सबसे गंभीर आरोप गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई को लेकर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार एलिजाबेथ ने 2011-12 के दौरान पाकिस्तान में काम किया था और उस दौरान उनका सीधा संपर्क 'अली तौकीर शेख' नाम के व्यक्ति से था, जिसे असम सरकार पाकिस्तानी एजेंट बता रही है। SIT की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलिजाबेथ ने 2013-14 के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक गोपनीय रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी, ताकि वहां की एजेंसियां भारत के खिलाफ अपनी रणनीति में बदलाव कर सकें।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एलिजाबेथ गोगोई अक्सर अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान की यात्रा करती थीं और इन यात्राओं की कोई आधिकारिक सूचना भारतीय एजेंसियों को नहीं दी जाती थी। इसके अलावा उन पर विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों, खासकर एफसीआरए कानून के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं। SIT रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एलिजाबेथ का संबंध जॉर्ज सोरोस से जुड़े नेटवर्क से हो सकता है और उन्होंने अपने पाकिस्तानी बैंक खाते से जुड़ी जानकारियां छिपाईं।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि SIT की जांच में कई ऐसे पहलू सामने आए हैं, जिनकी जांच राज्य स्तर पर संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले में इंटरपोल, विदेश मंत्रालय और संसद की कुछ गोपनीय फाइलों तक पहुंच की जरूरत है, जो केवल केंद्रीय एजेंसियां ही कर सकती हैं। इसी वजह से असम कैबिनेट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच NIA या CBI को सौंपी जाए।

दूसरी ओर, इन आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को "इस सदी की सबसे बड़ी फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस" करार देते हुए कहा कि यह पूरी कहानी किसी 'C-ग्रेड फिल्म' की स्क्रिप्ट जैसी है। गोगोई ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरमा अपनी राजनीतिक नाकामियों और कथित 'समय परिवर्तन यात्रा' से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

सूरजकुंड मेले में झूला हादसा, कर्तव्य निभाते शहीद हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद

फरीदाबाद के प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में शनिवार की शाम उस समय खुशियों का माहौल मातम में बदल गया, जब मेले में लगा 'सुनामी' नाम का झूला अचानक तकनीकी खराबी के चलते टूट गया। हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही पलों में चीख-पुकार मच गई और लोग इधर-उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। झूले पर उस समय करीब 19 लोग सवार थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से झूला हवा में एक ओर झुक गया और फिर तेज आवाज के साथ सीधे जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि राहत और बचाव कार्य के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।

घटना के तुरंत बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई। घायल लोग दर्द से कराहते रहे और उनके परिजन बदहवास हालत में इधर-उधर दौड़ते नजर आए। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अमले ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। इसी दौरान पलवल में तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, जो मेले में सुरक्षा ड्यूटी पर थे, बिना एक पल गंवाए झूले की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना झूले के नीचे और उसके ढांचे में फंसे लोगों

को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद लगातार लोगों को ढाढ़स बंधा रहे थे और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे थे। इसी दौरान वे स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके शहीद होने की खबर जैसे ही सामने आई, पुलिस विभाग और प्रशासन में शोक की लहर दौड़ गई। मेले में मौजूद लोग भी इस खबर से स्तब्ध रह गए कि एक पुलिस अधिकारी ने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी।

इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद का पुलिस सेवा में लंबा और अनुकरणीय करियर रहा है। वे वर्ष 1989 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे और करीब 36 वर्षों तक उन्होंने ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दीं। खास बात यह है कि वे इसी वर्ष मार्च महीने में सेवानिवृत्त होने वाले थे। सेवानिवृत्ति से कुछ ही सप्ताह पहले इस तरह कर्तव्य निभाते हुए उनका शहीद होना पूरे प्रदेश के लिए भावुक कर देने वाला क्षण बन गया है। उनके परिवार में इस घटना से गहरा शोक है, वहीं पुलिस महकमे में उन्हें एक बहादुर और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में याद किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेले में हुआ यह हादसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की बहादुरी की खुले शब्दों में सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जिस साहस और कर्तव्य भावना के साथ लोगों की जान बचाने की कोशिश की, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।

RSS अनुशासन सर्वोपरि मोहन भागवत उम्र पद और भाषा पर कहा स्पष्ट

नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी कार्यक्रम के दौरान सरसंघचालक मोहन भागवत के वक्तव्य ने न सिर्फ संगठन के भीतर बल्कि देश की राजनीति और वैचारिक विमर्श में भी नई चर्चा को जन्म दिया। 75 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पद छोड़ने को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने जिस सहजता, स्पष्टता और संगठनात्मक अनुशासन के साथ अपनी बात रखी, उसने संघ की कार्यसंस्कृति, नेतृत्व की सोच और उसकी दीर्घकालिक दृष्टि को एक बार फिर सामने ला दिया। मोहन भागवत ने साफ शब्दों में कहा कि वह स्वयं किसी पद से चिपके रहने में विश्वास नहीं रखते और जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनसे कहेगा, वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना पद छोड़ देंगे। उनके इस कथन में न तो कोई राजनीतिक गणना थी और न ही व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, बल्कि उसमें संघ की उस परंपरा की झलक थी, जहां व्यक्ति से बड़ा संगठन और पद से बड़ा कर्तव्य माना जाता है।

भागवत ने यह भी स्पष्ट किया कि 75 वर्ष की आयु को लेकर संघ में कोई कठोर या यांत्रिक नियम नहीं है, बल्कि यह एक परंपरा है, जिसका उद्देश्य अनुभव और ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 75 वर्ष पूरे किए, तब उन्होंने स्वयं अपनी स्थिति संगठन के सामने रखी थी, लेकिन संघ के शीर्ष नेतृत्व और विभिन्न प्रांतों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनसे आग्रह किया कि वे अभी भी सक्रिय भूमिका में बने रहें। यह निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि सामूहिक विचार-विमर्श और सहमति का परिणाम था। इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी समझाया कि संघ में सरसंघचालक का चयन चुनाव प्रक्रिया से नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक संगठन में काम करने वाले स्वयंसेवकों, प्रांतीय और क्षेत्रीय प्रमुखों की सहमति से नेतृत्व तय होता है। यह प्रक्रिया संघ की उस संस्कृति को दर्शाती है, जहां नेतृत्व संघर्ष या प्रचार से नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और विश्वास से उभरता है।

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में हल्के हास्य के साथ यह भी कहा कि संघ में रिटायरमेंट जैसी कोई अवधारणा नहीं है। यहां स्वयंसेवक से अंतिम सांस तक काम लिया जाता है, बशर्ते वह कार्य करने में सक्षम हो और संगठन को उसकी आवश्यकता हो। यह कथन सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर संघ की उस सोच का सार छिपा है, जिसमें जीवन को एक निरंतर साधना और समाज के लिए समर्पण के रूप में देखा जाता है। संघ के लिए काम करना कोई नौकरी नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है, जहां उम्र केवल एक संख्या होती है और अनुभव को सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है।

अपने वक्तव्य में भागवत ने भाषा के मुद्दे पर भी संघ का रुख बेहद स्पष्ट शब्दों में रखा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यभाषा नहीं बन सकती, क्योंकि यह भारत की मूल भाषा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि जहां आवश्यकता हो, वहां अंग्रेज़ी के प्रयोग से संघ को कोई परहेज नहीं है। उनका कहना था कि अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ होना आज के समय की जरूरत है, खासकर वैश्विक संवाद और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा या भारतीय भाषाओं को भूल जाएं। भागवत के इस विचार में भाषाई राष्ट्रवाद की वह भावना झलकती है, जिसमें अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक दुनिया से संवाद करने की बात कही जाती है।

उन्होंने इस बात पर भी आत्ममंथन किया कि संघ अपने प्रचार-प्रसार में अपेक्षाकृत पीछे रहा है। भागवत ने स्वीकार किया कि संघ का मूल कार्य प्रचार करना नहीं, बल्कि संस्कार देना है। स्वयंसेवकों के चरित्र निर्माण, सामाजिक समरसता और राष्ट्रभाव के विकास को संघ हमेशा से अपनी प्राथमिकता मानता रहा है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अत्यधिक प्रचार से प्रसिद्धि आती है और प्रसिद्धि से अहंकार पैदा होने का खतरा रहता है, जो किसी भी संगठन या व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह टिप्पणी आज के उस दौर में विशेष महत्व रखती है, जहां सोशल मीडिया और चौबीसों घंटे की खबरों की होड़ में प्रचार को ही सफलता का पैमाना मान लिया गया है।

मोहन भागवत का यह पूरा वक्तव्य दरअसल संघ की आंतरिक कार्यशैली और उसके मूल सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। संघ में पद को सत्ता या विशेषाधिकार का साधन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का माध्यम माना जाता है। यही कारण है कि सरसंघचालक जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति भी यह कहने में संकोच नहीं करते कि संगठन का आदेश उनके लिए सर्वोपरि है। इस सोच का असर संघ से जुड़े अनुषांगिक संगठनों और व्यापक सामाजिक-राजनीतिक परिवेश पर भी दिखाई देता है, जहां नेतृत्व को व्यक्ति केंद्रित नहीं, बल्कि विचार केंद्रित रखने की कोशिश की जाती है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भागवत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश में उम्र, पद और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बहसें तेज रहती हैं। विभिन्न दलों में शीर्ष नेतृत्व की उम्र को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन संघ के संदर्भ में भागवत का रुख यह संकेत देता है कि यहां निर्णय व्यक्ति की इच्छा से अधिक संगठन की आवश्यकता और सामूहिक विवेक पर आधारित होते हैं। इससे संघ की छवि एक ऐसे संगठन की बनती है, जहां अनुशासन और परंपरा केवल शब्द नहीं, बल्कि व्यवहार में उतरे हुए मूल्य हैं।

भाषा के मुद्दे पर उनका रुख भी व्यापक सांस्कृतिक विमर्श से जुड़ा हुआ है। भारत जैसे बहुभाषी देश में अंग्रेज़ी की भूमिका को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही भारतीय भाषाओं की उपेक्षा भी एक बड़ी चिंता है।

संपादकीय

दिल्ली के लापता लोग

पिछले दिनों इस खबर ने दिल्ली और देश के लोगों को चौंकाया कि इस साल जनवरी माह में ही देश की राजधानी में 800 लोग लापता पाए गए, जिसमें महिला, बच्चे व अन्य वयस्क भी शामिल हैं। जैसा कि स्वाभाविक था दिल्ली में लापता लोगों का आंकड़ा सामने आने के बाद आम लोगों में चिंता व्याप्त हो गई। प्रशासनिक स्तर पर भी इस समस्या की ओर अधिकारियों का ध्यान गया। बेलगाम सोशल मीडिया पर तो इन आंकड़ों पर अपनी-अपनी सुविधा और राजनीतिक हितों के मद्देनजर व्याख्या और बयानबाजी सामने आने लगी। पब्लिक फोरम पर कहा जाने लगा कि यह दिल्ली की कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद घर से निकलने के बाद सुरक्षा इंतजामों को लेकर तमाम तरह की सलाहें दी जाने लगीं। कुछ लोग देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगे। कुछ लोगों में भय से जुड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। लेकिन इस बाबत दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़े भी अधिक चिंता बढ़ाने वाले नजर आए। प्रथम दृष्टया यह खबर परेशान करने वाली है, लेकिन पड़ताल में पाया गया कि यह स्थिति पिछले कुछ सालों के आंकड़ों के ही अनुरूप है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्थिति की पुनरावृत्ति ही है। लेकिन यदि बीते कुछ सालों में लापता होने वाले लोगों की संख्या पर नजर डालें तो कहा जाता है कि इस साल जनवरी में सामने आई लापता लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। इस बाबत दिल्ली पुलिस का कहना है कि जनवरी 26 में कुल 1,777 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम दृष्टया यह संख्या भले ही बढ़ी लगे, लेकिन जब पिछले दो सालों के आंकड़ों से इसकी तुलना की जाती है तो नई तस्वीर उभरती है। दरअसल, इन आंकड़ों की तह में जाएं तो दिल्ली का विशाल इलाका व सघन जनसंख्या घनत्व भी इसके मूल में है।

दरअसल, एक बड़ी आबादी रोजगार व अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आती-जाती रहती है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में करीब 24,893 लोग लापता हुए थे। यानी एक माह में औसतन 2,074 लोग। वहीं साल 2025 में ये संख्या 24,508 लोग लापता हुए। अर्थात् हर माह 2,042 लोग गुम हुए। इस दृष्टि से जनवरी, 26 का आंकड़ा इस संख्या से कम है। सवाल है कि 2026 के पहले माह के आंकड़ों को लेकर भय क्यों व्याप्त हुआ? दरअसल, पहले पंद्रह दिनों के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में हर रोज 54 लोग लापता हो रहे थे। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद लोगों ने इसके मूल में किसी संकट को देखा। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये आंकड़े स्थायी गुमशुदगी के नहीं होते। कुछ लोग अल्पकाल के लिए कहीं चले जाते हैं और देर रात तक घर भी लौट आते हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन और ऐप आधारित सिस्टम के जरिये लोग जल्दबाजी में अपने परिजनों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। मसलन यदि कोई बच्चा किसी कारणवश स्कूल से लौटने में देर कर दे, कोई व्यक्ति कुछ घंटों तक फोन संपर्क से कट जाए या कोई बुजुर्ग भटकने पर देर से घर पहुंचे तो लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। ये कथित गुमशुदा लोग कुछ समय बाद घर तो लौट आते हैं, लेकिन लोग पुलिस डेटा को अपडेट नहीं करते। फलस्वरूप पुलिस आंकड़ों में उनकी गुमशुदगी बनी रहती है। पुलिस का दावा है कि लापता लोगों को खोजने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। साल 2016 में जो 23,409 लोग लापता हुए थे, उनमें से करीब 85 फीसदी नौ साल के भीतर मिल गए। साल 2025 में दर्ज मामलों में 63 फीसदी लोगों को भी एक साल के भीतर तलाश लिया गया। दलील है कि कई जटिल मामलों में तलाश का काम एक साल तक पूरा नहीं हो पाता। अन्य राज्यों में उनकी तलाश में समय लगता है। फिर भी पुलिस का दावा है कि दिल्ली के लापता लोगों की संख्या का आंकड़ा दुनिया के कई विकसित देशों से बेहतर स्थिति में है।

बेरोजगारी भी बढ़ा सकता है खाद्य पदार्थों का आयात

> ऐसे समय में जब घरेलू खेती पहले से ही संत्रास में है, किसानों को मंडियों में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 30 से 40 फीसदी कम दाम मिल रहे हैं, भारत के विशाल बाज़ार को सस्ते और बहुत ज़्यादा सब्सिडी वाले खेती उत्पादों के लिए और खोलने से खेती-बाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

शेक्सपियर के नाटकों में द्वंद्वात्मक कथानक की तरह, एक बड़ी दुविधा यह है कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जहां एक ओर अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस ने भारत के साथ एक बढ़िया व्यापार संधि -'अमेरिकी किसानों के लिए फायदेमंद है'- के लिए अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वाणिज्य मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी अमेरिका के साथ 'ऐतिहासिक संधि' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और दोहराया है कि यह करते वक्त भारत के संवेदनशील कृषि एवं डेयरी क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है।

क्या यह दोनों लोकतंत्रों के लिए 'परस्पर जीत' वाली स्थिति है या यह जोर-जबरदस्ती और मनमानी का नतीजा है, इसकी पुष्टि तो विवरण से ही हो पाएगी। लेकिन जो बातें सार्वजनिक तौर पर चली हुई हैं, उन्होंने पहले ही देशभर की किसान यूनियनों की रीढ़ में सिहरन की लहर दौड़ा दी है। उनके पास ऐसी चिंता करने के लिए पर्याप्त कारण भी हैं। ऐसे समय में जब घरेलू खेती पहले से ही संत्रास में है, किसानों को मंडियों में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 30 से 40 फीसदी कम दाम मिल रहे हैं, भारत के विशाल बाज़ार को सस्ते और बहुत ज़्यादा सब्सिडी वाले खेती उत्पादों के लिए और खोलने से खेती-बाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी किसानों को पहले से ही हर साल भारी सब्सिडी मिलती है, जो कि तकरीबन 66,314 डॉलर प्रति किसान वार्षिक जितनी है (एग्रीकल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट सर्वे, 2020), यह उन्हें उतार-चढ़ावों से बचाती है। इसके अलावा, अमेरिकी प्रशासन वर्ष 2026 में फार्मर्स ब्रिज असिस्टेंस प्रोग्राम (एफबीए) के तहत किसानों को होने वाले प्रति एकड़ नुकसान की भरपाई हेतु 12 बिलियन डॉलर की मदद उत्पाद भुगतान

मद के तहत देने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने इसको 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' का नाम दिया है। ऐसे में जब अमेरिका भारत व्यापार संधि के विवरण का अभी इंतज़ार है, अमेरिका और भारत, दोनों पक्ष बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। ब्रुक रोलिंस ने तो सोशल मीडिया पर यह तक कह डाला है कि इस समझौते से 'भारत के विशाल बाज़ार को अमेरिकी कृषि उत्पादों का अधिक निर्यात हो पाएगा, जिससे कीमतें ऊपर उठेंगी और ग्रामीण अमेरिका में अधिक नकदी आएगी'। यह कथन मोटे तौर पर व्यापार समझौते की शर्तों के मुताबिक है, जिसका जिक्र ट्विटर पर अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था कि अमेरिका में आयात होने वाले भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50 से घटाकर 18 परसेंट कर दी गई है और भारत में नॉन-टैरिफ बैरियर हटाने के अतिरिक्त अमेरिकी निर्यात पर आयात कर शून्य कर दिया गया जाएगा। इस बीच, भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को भरोसा दिला रहे हैं कि यह समझौता किसानों के हितों को 'सुरक्षित' रखने के बाद ही किया गया है।

इन भरोसे के बावजूद, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की खबर ने पहले ही किसान समुदाय को परेशान कर डाला है। भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए, जो कोई अन्य जानकारी देने से बच रही है, कई किसान नेताओं ने शक जताया है कि क्या किसानों के हितों की रक्षा में वास्तव में हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में चेतावनी दी है कि आयात शुल्क शून्य होने से सस्ते आयातित उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी, और इसलिए 12 फरवरी से नए विरोध प्रदर्शनों की धमकी दी है। किसान नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन 2020-21 के विरोध प्रदर्शनों की तर्ज पर होंगे।

किसान समुदाय को इस बात का भी गुस्सा है कि बजट-2026 में कृषि आय को बढ़ाने के लिए ज़रूरी उपायों पर ज़्यादातर चुप्पी रही है, और पहले से ही संकट झेल रहे कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए लाल लकीर कहां खींची जाए, इस पर किसानों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया है। इसके अलावा, सबसे अमीर व्यापारिक समूह, ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारतीय किसानों को 2000-01 और 2024-25 के बीच कुल मिलाकर 111 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लिहाजा किसानों के लिए एक और बड़ा झटका सहना मुश्किल होगा। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवान संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने चेतावनी दी है 'यह असहाय किसान समुदाय पर बड़े हथौड़े की मार जैसा होगा'। उन्होंने डर जताया कि यूरोपियन यूनियन और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते की वजह से सेब को जिस स्तर पर भारतीय बाजार में घुसपैठ मिल गई है, वह अभूतपूर्व है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में सेब उद्योग को भय सता रहा है कि उसका अंत व्यवस्थात्मक ढंग से होने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी सेब को शून्य आयात शुल्क पर आने की इजाज़त दी गई, तो पहाड़ी राज्यों की सेब आर्थिकी बर्बाद हो जाएगी। उधर, कपास, सोया और प्याज उगाने वाले किसान पहले से ही कुछ सालों से कम कीमतों से जूझ रहे हैं, और शून्य आयात शुल्क की वजह से बाजार में सस्ती आयातित उत्पाद आने से भारतीय किसानों के फसल के दाम और गिरने की आशंका है। यह स्थिति अंततः उन्हें खेती छोड़ने को मजबूर कर देगी।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति हर साल 500 बिलियन डॉलर मूल्य का अमेरिकन निर्यात होने की बात कह रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, तकनीक, कोयला और खेती के अलावा दूसरे क्षेत्र शामिल हैं, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि निर्यात का यह आंकड़ा शायद अगले 5 सालों का है यानी 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका से होने वाले सकल निर्यात में कृषि उत्पाद, डेयरी और उससे जुड़े क्षेत्र ही शामिल होंगे। जबकि, हमारे यहां होने वाले आयात में सबसे बड़ा हिस्सा अनाज, कॉटन, दालें, प्याज़, सोयाबीन और कई तरह की वाइन, शराब, फल, सब्जियां, बादाम और दूसरे मेवों का रहने की उम्मीद है। सूचना के अनुसार, कुछ चीज़ें, मसलन कपास, दालें और प्याज़ में 'कोटा एक्सेस' प्रावधान होगा। लेकिन यह चेतावनी है कि खाद्य पदार्थ आयात करना बेरोजगारी की आमद जैसा है।

कपास का ही मामला लें। सितंबर और दिसंबर, 2025 के बीच कपास आयात पर 11 फीसदी शुल्क हटाने से सस्ते कपास की आमद हुई, जिससे घरेलू कीमतें गिर गईं। जहां कपड़ा उद्योग कम दाम से खुश था, वहीं किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। तीन महीनों में ही आयात 30 लाख गांठें बढ़ गया और भारतीय कपास का दाम 1,000 रुपये से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गया। इसके अतिरिक्त, चूंकि समझौते के अनुसार नॉन-टैरिफ बैरियर हटाने होंगे, और भारत में इस श्रेणी में आते उत्पादों की संख्या कुछ सौ है, ऐसे में भारत अमेरिकी दूध आयात से उपभोक्ता को कैसे दूर रख पाएगा, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अमेरिकी गायों की खुराक में ब्लड-मील और अन्य मांसाहारी अवयव डाले जाते हैं।

असल में, ट्रंप जिस तरह विकासशील देशों के गले से नयी व्यापार व्यवस्था उतार रहे हैं और यूरोपियन यूनियन पर भी नज़र रख रहे हैं, वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है। 1995 में यह संस्था बनने के बाद से अमेरिका जो हासिल नहीं कर पाया था, अब उसे बांह मरोड़कर पाने का इंतजाम कर लिया है। दबाव में आकर राष्ट्रों के झुकने से, एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है। 'शक्तिशाली सदा सही होता है' वाली हिमाकत कब तक चलेगी, यह तो वक्त ही बताएगा।

प्रेरणा

संघर्ष, विज्ञान और संकल्प से जन्मा महान आविष्कार

मानव सभ्यता के विकास में विज्ञान और तकनीक की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण रही है, उतनी ही महत्वपूर्ण उन वैज्ञानिकों और आविष्कारकों की जीवन-कथाएँ भी हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जीवित रखा। ऐसे ही एक महान इंजीनियर और आविष्कारक थे रुडोल्फ डीजल, जिनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि सच्चा समर्पण, गहरी जिज्ञासा और अडिग संकल्प किसी भी व्यक्ति को इतिहास में अमर बना सकते हैं। उनका नाम आज एक इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे संघर्ष, चोट, असफलता और फिर अदम्य साहस की लंबी कहानी छिपी है।

रुडोल्फ डीजल का बचपन साधारण था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने यह समझ लिया था कि वे अपना जीवन मशीनों और तकनीक को समझने में बिताना चाहते हैं। मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता-पिता को यह बता दिया था कि वे बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे। यह निर्णय किसी क्षणिक उत्साह का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके भीतर पल रही वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा का स्वाभाविक निष्कर्ष था। उस समय अधिकांश किशोर भविष्य को लेकर स्पष्ट नहीं होते, लेकिन डीजल का लक्ष्य बिल्कुल साफ था।

उच्च शिक्षा के लिए वे जर्मनी गए, जहाँ उस दौर में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक शोध का वातावरण तेजी से विकसित हो रहा था। जर्मनी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने न केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि प्रयोगों और व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से मशीनों की वास्तविक कार्यप्रणाली को भी समझा। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका जीवन प्रयोगशाला और वर्कशॉप तक सिमट गया। वे घंटों तक इंजन, ईंधन और ऊर्जा के सिद्धांतों पर विचार करते रहते थे। उनका मानना था कि उस समय प्रचलित इंजन तकनीक में सुधार की अपार संभावनाएँ हैं।

उस समय भाप इंजन का व्यापक उपयोग हो रहा था, लेकिन ये इंजन भारी, कम दक्ष और ईंधन की अधिक खपत करने वाले थे। डीजल इस स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि ऐसा इंजन विकसित किया जाए जो कम ईंधन में अधिक शक्ति दे और अधिक टिकाऊ हो। इसी सोच ने उन्हें नए-नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उनकी वर्कशॉप में दिन-रात प्रयोग चलते रहते थे। कई बार प्रयोग असफल होते, लेकिन वे हर असफलता को सीख का एक अवसर मानते थे।

इसी प्रयोगात्मक दौर में एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। जब वे अपने इंजन पर काम कर रहे थे, अचानक एक जोरदार विस्फोट हो गया। इस विस्फोट ने पूरी वर्कशॉप को तहस-नहस कर दिया। मशीनें टूट गईं, दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और स्वयं रुडोल्फ डीजल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। यह केवल शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि उनके वर्षों की मेहनत भी इस हादसे में नष्ट हो गई थी।

किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह हादसा सपनों के टूटने जैसा होता, लेकिन डीजल असाधारण थे। अस्पताल में रहते हुए भी उनका मन शांत नहीं था। वे लगातार यह सोचते रहते थे कि गलती कहाँ हुई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। उन्होंने इस दुर्घटना को अपनी विफलता नहीं माना, बल्कि इसे अपने ज्ञान को और गहरा करने का अवसर समझा। उनके भीतर यह दृढ़ विश्वास था कि विज्ञान का रास्ता जोखिम भरा जरूर है, लेकिन पीछे हटने का नहीं होता।

लंबे उपचार के बाद जब वे स्वस्थ हुए, तो सबसे पहले वे अपनी वर्कशॉप लौटे। टूटी हुई मशीनें और बिखरा हुआ सामान उनके उत्साह को कम नहीं कर सका। उन्होंने फिर से नए सिरे से काम शुरू किया, इस बार पहले से अधिक अनुभव और सावधानी के साथ। उन्होंने इंजन के दहन सिद्धांत पर गहन अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि ईंधन को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसी चिंतन से उच्च संपीड़न पर आधारित इंजन का विचार सामने आया, जिसमें ईंधन स्वयं प्रज्वलित हो जाता है।

लगातार प्रयासों के बाद उनके प्रयोग सफल होने लगे। उन्होंने ऐसे इंजन का विकास किया जो पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली, अधिक दक्ष और अधिक विश्वसनीय था। यही इंजन आगे चलकर डीजल इंजन के नाम से जाना गया। यह आविष्कार औद्योगिक दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। जहाजों, रेलगाड़ियों, भारी वाहनों और बाद में बिजली उत्पादन में इस इंजन का उपयोग तेजी से बढ़ा। उद्योगों को एक ऐसी तकनीक मिली जिसने उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया।

रुडोल्फ डीजल का योगदान केवल एक इंजन तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक सोच और व्यावहारिक प्रयोग के संयोजन से समाज की बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। उनका इंजन औद्योगिक विकास का मजबूत आधार बना और विश्व अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। आज के आधुनिक डीजल इंजन भले ही तकनीकी रूप से अत्यंत उन्नत हों, लेकिन उनके मूल सिद्धांत वही हैं, जिन्हें डीजल ने अपने अथक परिश्रम से विकसित किया था।

उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती। विस्फोट जैसी भयावह दुर्घटना के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा आविष्कार केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास से जन्म लेता है। आज की नई पीढ़ी, जो तेजी से बदलती तकनीक और कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने लक्ष्य खोज रही है, उनके जीवन से प्रेरणा ले सकती है।

रुडोल्फ डीजल आज भले ही हमारे बीच न हों, लेकिन उनका नाम और उनका आविष्कार आज भी दुनिया को गति दे रहा है। हर वह मशीन जो डीजल इंजन के सिद्धांत पर चलती है, उनके संघर्ष, समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टि की कहानी सुनाती है। यही कारण है कि रुडोल्फ डीजल केवल एक आविष्कारक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के शाश्वत स्रोत बने हुए हैं।

चुनौती का सामना करें

भारतीय उद्योग, यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार समझौता बहुत महत्वपूर्ण

इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की दिल्ली में उपस्थिति केवल भारत और यूरोप के बीच के मधुर होते संबंधों को ही नहीं बयान कर रही थी, बल्कि इन संबंधों को आगे बढ़ाने की पहल को भी रेखांकित कर रही थी। अंततः गणतंत्र दिवस के अगले दिन यूरोपीय संघ और भारत के बीच वह व्यापार समझौता हो गया, जिसकी व्यापक चर्चा हो रही थी और जिसे सभी व्यापार समझौतों की जननी कहा जा रहा था।

इस समझौते ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। प्रारंभ में अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं थी, लेकिन जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के साथ व्यापार समझौते पर सहमति बन जाने की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को 18 प्रतिशत करने जा रहा है।

उनकी इस घोषणा का भारतीय प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया। चूंकि गत दिवस इस समझौते की रूपरेखा सामने आ गई, इसलिए माना जा रहा है कि अगले माह इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की तरह अमेरिका से होने वाला व्यापार समझौता इसलिए विशेष है, क्योंकि इसे लेकर असमंजस था कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो पाएगा या नहीं?

भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता इसलिए हो सका, क्योंकि एक ओर जहां भारत अमेरिकी राष्ट्रपति के रवैये से चिंतित था, वहीं दूसरी ओर यूरोप के देश भी। इस समझौते का एक कारण यह भी रहा कि पिछले कुछ समय में भारत ने यूरोप के प्रमुख देशों फ्रांस और जर्मनी के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ किए हैं।

इसके अलावा हाल के समय में भारत ने ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान और यूएई के साथ भी व्यापार समझौते किए हैं। कुछ अन्य देशों से भी भारत की व्यापार समझौते संबंधी वार्ताएं अंतिम चरण में हैं। इन देशों में कनाडा भी है, जिसके इन दिनों अमेरिका से रिश्ते खराब चल रहे हैं। यूरोप को व्यापार के मामले में भारत का साथ लेना इसलिए आवश्यक महसूस हो रहा था, क्योंकि यहां के देश कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

वैसे तो यूरोपीय देश संपन्न हैं, लेकिन उनके यहां छोटी-मोटी चीजों का उत्पादन बंद सा हो गया है और वे हाईटेक उत्पादों और सेवाओं पर ही अधिक केंद्रित हैं। यूरोपीय देश अप्रवासियों के आगमन के चलते सामाजिक उथल-पुथल का भी सामना कर रहे हैं। वहां के कई देशों में अप्रवासियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। यूरोप भले ही दो दर्जन से अधिक देशों की एक इकाई हो, पर वहां के कुछ देश अत्यधिक विकसित हैं तो कुछ विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे विकासशील देश भारत से व्यापार को अपने लिए और लाभप्रद मान रहे हैं।

जिस तरह भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते ने सुर्खियां बटोरीं, उसी तरह भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते को लेकर भी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। समझौते पर दोनों देशों के साझा बयान ने चर्चा को और तेज कर दिया है। भारत अमेरिका के साथ यथाशीघ्र व्यापार समझौते के लिए इसलिए प्रयत्नशील था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारतीय निर्यातक मुश्किल में थे। यह व्यापार समझौता ट्रंप के रवैये के कारण ही अटका हुआ था।

वे इससे खफा थे कि भारत उनके न चाहने के बाद भी रूस से तेल खरीद रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में भारत ने रूस से तेल खरीद में कटौती की थी, लेकिन ट्रंप किसी तरह की नरमी नहीं दिखा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जब वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया और वहां अपनी कठपुतली सरकार स्थापित कर दी तो स्थितियां तेजी से बदलीं। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रंप ने यह घोषणा की कि अब उसके तेल की बिक्री उनके हिसाब से होगी।

इस घोषणा के कुछ दिनों बाद भारतीय प्रधानमंत्री और वेनेजुएला की राष्ट्रपति के बीच वार्ता भी हुई। इसी वार्ता के चंद दिन बाद ट्रंप ने भारत से व्यापार समझौते पर सहमति बन जाने के साथ यह भी घोषणा की कि अब भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और रूस से तेल खरीद बंद करेगा। चूंकि भारत पहले भी वेनेजुएला से तेल खरीदता था, इसलिए यदि वह फिर से उससे तेल खरीद शुरू कर देता है तो इसमें कोई नई-अनोखी बात नहीं, लेकिन देखना यह है कि क्या वह रूस से पूरी तौर पर तेल खरीदना बंद करेगा?

यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते और अमेरिका के साथ होने वाले इसी तरह के समझौते के बाद भारत सरकार के साथ भारतीय कारोबारियों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि इन समझौतों का अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाया जाए। चूंकि यूरोप के देशों ने हर मामले में अपने मानक ऊंचे कर रखे हैं, इसलिए भारतीय कारोबारियों को इस पर गौर करना होगा कि उनके उत्पाद और उनकी सेवाएं वहां के मानकों पर खरी उतर सकें।

अभियान

केदारनाथ के बाद बदरीनाथ धाम के लिए हेली सेवा से तीर्थयात्रा होगी सरल

उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए इसे अधिक सहज, सुरक्षित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रही है। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित चारधाम न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि भौगोलिक रूप से भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर निकलते हैं। सरकार लंबे समय से यह महसूस कर रही थी कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सीमित भौगोलिक संसाधनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसी सोच के तहत पहले केदारनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवाएं शुरू की गईं और अब उसी क्रम में बदरीनाथ धाम के लिए भी हेलीकॉप्टर शटल सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिससे चारधाम यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है।

चारधाम यात्रा का मौसम जैसे ही शुरू होता है, पहाड़ी सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। संकरे रास्ते, ऊंचे पहाड़, अचानक बदलता मौसम और कई बार भूस्खलन जैसी घटनाएं यात्रियों की परेशानी बढ़ा देती हैं। सड़क मार्ग से बदरीनाथ या केदारनाथ तक पहुंचने में कई बार घंटों नहीं बल्कि पूरा दिन लग जाता है। बुजुर्ग श्रद्धालु, बीमार लोग और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवार अक्सर इन कठिनाइयों से जूझते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने हवाई सेवाओं को यात्रा का अहम हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। केदारनाथ के लिए शुरू हुई हेली सेवाओं ने यह साबित कर दिया कि यदि सही योजना और सुरक्षा व्यवस्था के साथ काम किया जाए, तो हवाई यात्रा तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत बन सकती है। केदारनाथ हेली सेवाओं की सफलता के बाद अब बदरीनाथ धाम के लिए भी इसी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बदरीनाथ के लिए प्रस्तावित हेली शटल सेवा गौचर से संचालित होगी। गौचर से बदरीनाथ तक की हवाई दूरी को हेलीकॉप्टर महज लगभग 22 मिनट में तय करेगा, जबकि यही सफर सड़क मार्ग से कई घंटों का होता है। इस सेवा का अनुमानित एकतरफा किराया लगभग 11 हजार रुपये रखा गया है। यह किराया केदारनाथ हेली सेवाओं की तुलना में थोड़ा अधिक है, जिसका कारण उड़ान की लंबी अवधि और परिचालन लागत बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि समय की बचत, सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस सेवा को अपनाएंगे। इस हेली शटल सेवा का संचालन थंपी एविएशन को सौंपा गया है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी यूकाडा इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। यूकाडा का प्रयास है कि हवाई सेवाएं पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और अनुशासित तरीके से संचालित हों। बदरीनाथ हेली सेवा की बुकिंग भी केदारनाथ की तरह आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। इससे श्रद्धालुओं को घर बैठे टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी और दलालों या अवैध बुकिंग जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी। ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यात्रा की योजना बनाना भी आसान हो जाएगा।

पिछले वर्षों में हेली सेवाओं के दौरान हुई कुछ दुर्घटनाओं ने प्रशासन को सुरक्षा मानकों पर और गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद यूकाडा ने हेली सेवाओं के संचालन में कई सख्त फैसले लिए। उड़ानों की संख्या सीमित की गई, मौसम की निगरानी को अधिक मजबूत किया गया और पायलटों तथा तकनीकी स्टाफ के लिए कड़े दिशा-निर्देश लागू किए गए। किरायों में भी वृद्धि की गई ताकि सुरक्षा से जुड़े अतिरिक्त इंतजाम किए जा सकें। बदरीनाथ के लिए शुरू होने वाली हेली सेवाओं में भी इन्हीं अनुभवों को ध्यान में रखा जा रहा है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि किसी भी स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा और मौसम की अनुकूलता के आधार पर ही उड़ानों की अनुमति दी जाएगी।

यूकाडा के मुख्य अधिशासी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया है कि बदरीनाथ के लिए हेली शटल सेवा के टेंडर पूरे किए जा चुके हैं और चारधाम यात्रा के दौरान गौचर से बदरीनाथ के लिए यह सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह नियंत्रित और निगरानी में रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए उड़ानों के समय और संख्या को लेकर लचीलापन रखा जाएगा। यदि मौसम खराब होता है तो सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका भी जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार के जोखिम से बचा जा सके। केदारनाथ हेली सेवाओं के किराये को लेकर भी इस वर्ष विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले वर्ष दूसरे चरण की हेली सेवाओं में लगभग 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी और किरायों में करीब 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई थी। इस वर्ष केदारनाथ धाम के लिए नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन चूंकि पिछले वर्ष किराये में पहले ही वृद्धि हो चुकी थी, इसलिए इस बार किराया लगभग उसी स्तर पर बनाए रखने की योजना है। हालांकि वास्तविक दरें टेंडर खुलने के बाद ही स्पष्ट होंगी। प्रशासन का मानना है कि सीमित संख्या में लेकिन सुरक्षित हेली सेवाएं संचालित करना ही बेहतर विकल्प है।

बदरीनाथ के साथ-साथ यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली शटल सेवाएं शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि यमुनोत्री के मामले में कुछ तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिसके कारण वहां सेवाएं शुरू करने में देरी हो रही है। हेलीपैड की स्थिति, उड़ान मार्ग और मौसम संबंधी पहलुओं पर अभी अध्ययन जारी है। सरकार का प्रयास है कि इन समस्याओं का समाधान कर आने वाले समय में यमुनोत्री के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू की जा सकें, ताकि चारों धामों की यात्रा अधिक संतुलित और सुविधाजनक हो सके। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की धार्मिक पहचान के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था का भी एक मजबूत आधार है। यात्रा सीजन के दौरान होटल, ढाबे, टैक्सी चालक, घोड़ा-खच्चर संचालक और स्थानीय व्यापारी बड़ी संख्या में रोजगार से जुड़ते हैं। हेली शटल सेवाओं के विस्तार से जहां एक ओर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि सरकार यह भी ध्यान रख रही है कि हवाई सेवाओं के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और पहाड़ी क्षेत्रों की संवेदनशीलता बनी रहे।

कुल मिलाकर, केदारनाथ के बाद बदरीनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवा की शुरुआत चारधाम यात्रा के इतिहास में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। यह पहल आस्था और आधुनिक तकनीक के संतुलन का उदाहरण है। इससे न केवल यात्रा का समय और कठिनाई कम होगी, बल्कि श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा अनुभव भी मिलेगा। यदि यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है और उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर सकता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

आत्मविश्वास से गढ़ी जाती है पहचान, डर से नहीं बनता कोई भविष्य

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे Gen-Z NRI छात्रों से संवाद के दौरान युवाओं के मन में चल रहे सवालों, असमंजस और मानसिक दबावों पर खुलकर बात की और एक साफ संदेश दिया कि भविष्य डर से नहीं, आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच से तय होता है। राहुल गांधी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए 6 मिनट 37 सेकेंड के इस संवाद ने न केवल प्रवासी भारतीय युवाओं का ध्यान खींचा, बल्कि देश-विदेश में पढ़ने और काम करने वाली युवा पीढ़ी के अनुभवों और चिंताओं को भी आवाज दी। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने राजनीति से इतर जीवन, पहचान, उद्देश्य, असफलता और आत्म-स्वीकृति जैसे मुद्दों को बेहद सहज और मानवीय अंदाज में सामने रखा।

राहुल गांधी ने युवाओं से संवाद की शुरुआत ही इस बात से की कि आज की Gen-Z दुनिया की सबसे ज्यादा जुड़ी हुई, लेकिन भीतर से उतनी ही उलझी हुई पीढ़ी है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के दबाव के बीच युवा अक्सर खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि वे कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह सवाल गलत नहीं हैं, बल्कि यही सवाल किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने की दिशा देते हैं। समस्या तब शुरू होती है, जब डर इन सवालों के जवाब ढूंढने से रोक देता है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर डर के आधार पर फैसले लिए जाएंगे तो जिंदगी सीमित हो जाएगी, लेकिन अगर आत्मविश्वास और ईमानदारी से अपने भीतर झांका जाए तो रास्ते खुद-ब-खुद खुलते चले जाते हैं।

संवाद के दौरान छात्रों ने राहुल गांधी से 'भारत जोड़ो यात्रा' को लेकर भी सवाल किए। राहुल गांधी ने इसे केवल एक राजनीतिक अभियान मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह उनके जीवन के सबसे गहरे अनुभवों में से एक था। उन्होंने बताया कि इस यात्रा ने उन्हें भारत को किताबों, रिपोर्टों या भाषणों से अलग, जमीन पर चलकर समझने का मौका दिया। यात्रा के दौरान हर धर्म, हर वर्ग और हर भाषा के लोग साथ चले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई—सभी ने एक-दूसरे की कहानियां सुनीं, साथ हंसे, साथ थके और साथ आगे बढ़े। राहुल गांधी के अनुसार, इस यात्रा ने यह एहसास कराया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और आपसी संवाद में है, न कि डर और विभाजन में। उन्होंने कहा कि जब लोग एक-दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तब समाज में दरारें पड़ती हैं, और 'भारत जोड़ो यात्रा' का उद्देश्य ही इन दरारों को भरना था।

युवाओं द्वारा पूछे गए सवालों में सफलता और असफलता का मुद्दा भी प्रमुख रहा। कई छात्रों ने यह स्वीकार किया कि वे असफल होने से डरते हैं और इसी डर के कारण कई बार नए मौके आजमाने से पीछे हट जाते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं मिलती। हर व्यक्ति गिरता है, ठोकर खाता है और फिर सीखकर आगे बढ़ता है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में असफलताएं और आलोचनाएं लगातार आती हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो उनसे सीखता है और खुद पर भरोसा बनाए रखता है। राहुल गांधी ने युवाओं से कहा कि असफलता को अपनी पहचान न बनने दें, बल्कि उसे सीखने का जरिया बनाएं।

बातचीत के दौरान पहचान और उद्देश्य का सवाल भी बार-बार सामने आया। कई Gen-Z छात्रों ने कहा कि वे प्रोफेशन और पैशन के बीच उलझन महसूस करते हैं। समाज और परिवार की अपेक्षाएं एक दिशा में खींचती हैं, जबकि दिल कुछ और करना चाहता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे अपनी सोच को दबाएं नहीं, बल्कि समय लेकर खुद को समझें। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता। जिंदगी में रास्ते बदलते रहते हैं और यह बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

मानसिक दबाव और एंग्जायटी जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी ने बेहद संवेदनशील अंदाज में बात की। उन्होंने माना कि आज की पीढ़ी पर जजमेंट और तुलना का दबाव पहले से कहीं ज्यादा है। सोशल मीडिया पर हर कोई खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, जिससे युवाओं में आत्म-संदेह बढ़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल तनाव बढ़ता है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे खुद से ईमानदार रहें, अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और जरूरत पड़ने पर मदद लेने से न हिचकें।

संवाद में कई छात्रों ने आत्मविश्वास की कमी को अपनी सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि वे अक्सर जज किए जाने के डर से अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह डर सभी में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके सामने रुक जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे परीक्षा में बैठने से पहले डर लगता है, लेकिन तैयारी और हिम्मत के साथ बैठने पर ही सफलता मिलती है, वैसे ही जिंदगी की चुनौतियों में भी खुद पर भरोसा करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि खुद पर जीत हासिल करना किसी भी बाहरी जीत से ज्यादा अहम है।

बातचीत के अंत में राहुल गांधी ने Gen-Z के लिए एक व्यापक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज अक्सर लोगों को लेबल में बांधने की कोशिश करता है—अच्छा, बुरा, सफल, असफल—लेकिन इन लेबल से बाहर निकलकर खुद को समझना सबसे जरूरी है। उन्होंने युवाओं को लचीला रहने, लगातार सीखते रहने और बदलते हालात के साथ खुद को ढालने की सलाह दी। राहुल गांधी ने कहा कि जिंदगी कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, इसमें मोड़ आते हैं और वही मोड़ इंसान को मजबूत बनाते हैं।

इस पूरे संवाद की भावना को राहुल गांधी ने तीन शब्दों में समेटते हुए कहा—ईमानदार सवाल, सच्चे जवाब और बिना किसी फिल्टर के संवाद। उनका कहना था कि जब युवा बिना डर के सवाल पूछते हैं और समाज उन्हें सच्चाई से जवाब देने का माहौल देता है, तभी एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी भविष्य की नींव पड़ती है। UAE में रहने वाले Gen-Z NRI छात्रों के साथ यह बातचीत केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह उस पीढ़ी के मन की आवाज बन गई, जो डर के बजाय आत्मविश्वास के सहारे अपनी पहचान और भविष्य गढ़ना चाहती है।

बजट के बाद बाजार की नब्ज समझने जुटे उद्योगपति, 'बजट से बुलियन तक' सेशन में कमोडिटी ट्रेंड्स पर मंथन

सूरत। केंद्रीय बजट 2026 के बाद कमोडिटी मार्केट में संभावित बदलावों और नए ट्रेंड्स को समझने के उद्देश्य से सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) द्वारा नानपुरा स्थित समृद्धि भवन में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। 'बजट से बुलियन तक – बजट 2026 के बाद कमोडिटी मार्केट के ट्रेंड्स को समझना' विषय पर आयोजित इस सेशन में उद्योग जगत, ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और बाजार की मौजूदा तथा भावी दिशा पर गंभीर चर्चा की।

सेमिनार की शुरुआत चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने कहा कि बजट के बाद कमोडिटी मार्केट में जो उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं, वे सीधे तौर पर उद्योगपतियों, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सिर्फ अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस जानकारी और विशेषज्ञों की राय के आधार पर निर्णय लेना बेहद जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, सरकार की नीतियां, टैक्स स्ट्रक्चर और बजट से जुड़े फैसले कमोडिटी मार्केट की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं और इसी कारण चैंबर समय-समय पर ऐसे ज्ञानवर्धक सेशन आयोजित करता है, ताकि सदस्य बदलते बाजार हालात के लिए तैयार रह सकें। इस सेशन के मुख्य वक्ता डी.आर. चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और देश के जाने-माने मार्केट एक्सपर्ट देवेन चोकसी रहे। उन्होंने बजट 2026 के बाद कमोडिटी मार्केट, विशेष रूप से सोना-चांदी, बेस मेटल्स और एनर्जी कमोडिटीज़ में संभावित रुझानों पर गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज का कमोडिटी मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पर ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स, महंगाई, डॉलर की स्थिति और जियो-पॉलिटिकल घटनाओं का सीधा असर पड़ता है। उन्होंने सरल और व्यावहारिक भाषा में समझाया कि कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले छोटे-छोटे बदलाव भी कमोडिटी प्राइस में बड़ा फर्क ला सकते हैं।

देवेन चोकसी ने निवेशकों को आगाह करते हुए कहा कि बजट के बाद बाजार में वोलैटिलिटी बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसी दौर में सही रणनीति अपनाकर बेहतर अवसर भी तलाशे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कमोडिटी मार्केट में निवेश करते समय लॉन्ग-टर्म विज़न, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और संतुलित सोच बेहद जरूरी है। भावनाओं में बहकर या शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव से घबराकर लिए गए फैसले नुकसान का कारण बन सकते हैं। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता रखें और बुलियन व अन्य कमोडिटीज़ को हेजिंग के रूप में देखें, न कि केवल त्वरित मुनाफे के साधन के तौर पर।

सेमिनार के दौरान सोने और चांदी के भाव, इंडस्ट्रियल मेटल्स की मांग, एनर्जी सेक्टर में वैश्विक घटनाक्रम और भारत की आर्थिक नीतियों के असर जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। देवेन चोकसी ने बताया कि आने वाले समय में महंगाई और ब्याज दरों की दिशा कमोडिटी मार्केट के लिए निर्णायक साबित होगी और निवेशकों को इन संकेतकों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। इस कार्यक्रम में चैंबर के ऑनरेरी ट्रेजरर सीए मितिश मोदी, कमेटी के सदस्य, बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इन्वेस्टर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स मौजूद रहे। कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा चैंबर के ग्रुप चेयरमैन कमलेश गजेरा ने प्रस्तुत की, जबकि पूरे सेशन का संचालन कैपिटल और कमोडिटी मार्केट कमेटी के एडवाइज़र केतन दलाल ने किया। उन्होंने चर्चा को संतुलित और संवादात्मक बनाए रखते हुए प्रतिभागियों को विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछने का अवसर दिया।

सेशन के अंत में आयोजित प्रश्न-उत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने कमोडिटी मार्केट से जुड़े कई व्यावहारिक सवाल उठाए, जिनका देवेन चोकसी ने विस्तार और स्पष्टता के साथ उत्तर दिया। निवेशकों ने इस सेशन को बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि बजट के बाद बाजार की सही दिशा समझने में यह सेमिनार मार्गदर्शक साबित हुआ। चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल जानकारीपूर्ण रहा, बल्कि बदलते आर्थिक माहौल में समझदारी भरे निवेश के लिए उद्योग और व्यापार जगत को नई दृष्टि भी दे गया।

बंगाल की राजनीति में 'लक्ष्मी भंडार' बना चुनावी हथियार, धमकी से गरमाया सियासी माहौल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज होते ही सियासत का तापमान भी लगातार चढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी सरकार की महत्वाकांक्षी 'लक्ष्मी भंडार' योजना अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के केंद्र में आ गई है। जहां एक ओर राज्य बजट में इस योजना की राशि बढ़ाकर महिलाओं को राहत देने का दावा किया गया है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक विधायक के बयान ने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ से TMC विधायक शौकत मोल्ला द्वारा दिए गए बयान को विपक्ष ने खुली धमकी करार दिया है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है।

दरअसल, ममता बनर्जी सरकार ने हाल ही में बजट में 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि इस कदम से राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। लेकिन विपक्षी दलों ने इसे सीधे तौर पर चुनावी 'फ्रीबीज' करार देते हुए सवाल उठाए हैं कि क्या यह फैसला चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसी बीच शौकत मोल्ला का बयान सामने आने से विवाद और गहरा गया।

भांगड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए शौकत मोल्ला ने कहा कि यदि वह चुनाव में हारते हैं तो संबंधित इलाकों में सरकारी सेवाएं और पैसे बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन क्षेत्रों से वह पहले हार चुके हैं, वहां पहले ही सरकारी पैसा बंद करवा दिया गया है। उनका बयान यहीं नहीं रुका। उन्होंने कहा कि "ममता बनर्जी पैसा देंगी और फिर उनकी बुराई की जाएगी, यह नहीं चलेगा।" साथ ही उन्होंने स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन ISF कार्यकर्ताओं के नाम मुख्यमंत्री कार्यालय (CMRO) तक पहुंचे हैं, उन्हें लक्ष्मी भंडार समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भांगड़ के चलतबेरिया, शानपुकुर और पोलरहाट-1 जैसे इलाकों में तृणमूल कांग्रेस को इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। शौकत मोल्ला के बयान को इसी हार से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष अब सरकारी योजनाओं को वोट से जोड़कर लोगों को डराने-धमकाने की राजनीति कर रहा है।

शौकत मोल्ला के बयान पर जब विवाद बढ़ा तो खुद तृणमूल कांग्रेस ने उससे दूरी बना ली। पार्टी प्रवक्ता तन्मय घोष ने साफ कहा कि यह पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है और विधायक व्यक्तिगत स्तर पर बोल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस अलीपुरद्वार और पूर्व मेदिनीपुर जैसी कई सीटों पर भी हारी है, लेकिन वहां सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को लगातार मिल रहा है। पार्टी ने यह संकेत देने की कोशिश की कि सरकारी योजनाएं किसी पार्टी या व्यक्ति की हार-जीत से नहीं जुड़ी हैं।

दूसरी ओर, विपक्ष ने इस बयान को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। भाजपा ने इसे गरीब और महिलाओं के अधिकारों से खिलवाड़ करार दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लोगों को डर और लालच के सहारे नियंत्रित करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो केंद्र के सहयोग से ऐसा बजट तैयार किया जाएगा, जो वास्तव में 'विकसित पश्चिम बंगाल' की दिशा में काम करेगा।

उत्तर भारत में मौसम का बदला मिज़ाज, कहीं धूप से राहत तो कहीं बारिश-बर्फबारी की दस्तक

नई दिल्ली। उत्तर भारत में मौसम धीरे-धीरे सर्दी की पकड़ ढीली करता नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली-एनसीआर में जहां तापमान में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, वहीं पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड कम होगी और दिन का तापमान धीरे-धीरे ऊपर जाएगा, जबकि पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम करवट ले सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम सामान्य बना रहने की संभावना है। सुबह के समय ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप निकलने से मौसम सुहावना हो जाएगा। उत्तर-पश्चिमी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लोगों को हल्की ठंड का अहसास जरूर कराएंगी, लेकिन कुल मिलाकर सर्दी का असर कमजोर पड़ता दिखेगा। मौसम विभाग ने 12 फरवरी तक दिल्ली में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि वायु गुणवत्ता लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 223, अशोक विहार में 248, बवाना में 231, जहांगीरपुरी में 242, मुंडका में 268 और नरेला में 254 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि लोधी रोड और मंदिर मार्ग जैसे कुछ इलाकों में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रही।

उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिज़ाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों तक छाए घने कोहरे का असर अब काफी कम हो गया है। पछुआ हवाओं के चलते सुबह और शाम हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन दिन के समय मौसम साफ और शुष्क है। मौसम विभाग ने राज्य में आज के लिए बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक अगले करीब तीन दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम बना रहेगा।

बिहार में भी ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है। दिन के समय गर्मी का अहसास होने लगा है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शनिवार को गोपालगंज राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश या कोहरे को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। साफ आसमान और हल्की हवाओं के कारण लोगों को दिन में राहत मिल रही है, हालांकि सुबह-शाम हल्की ठंड अभी बनी हुई है।

दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। हिमाचल प्रदेश में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है और कई इलाकों में शीतलहर का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 9 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। शनिवार को देहरादून और आसपास के इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहा और अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कल से पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल सकता है।

कुल मिलाकर उत्तर भारत में मौसम का यह दौर संक्रमण काल जैसा है, जहां मैदानी इलाकों में सर्दी धीरे-धीरे विदा ले रही है और पहाड़ों में अभी भी ठंड और बारिश-बर्फबारी की संभावना बनी हुई है।

कोटा में निर्माणाधीन इमारत का कहर, मलबे में दबे सपने और टूटा भरोसा

कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने एक बार फिर शहरी निर्माण की सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जवाहर नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा विहार इलाके में एक निर्माणाधीन दो मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्र समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मलबे में दबने से घायल हुए कुल 13 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जिनमें से 5 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि बाकी की हालत नाजुक बनी हुई है।

हादसा शनिवार रात करीब 8:45 बजे हुआ, जब इंदिरा विहार में स्थित यह दो मंजिला इमारत अचानक गिर पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ ही पलों में पूरी इमारत धूल और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। तेज आवाज के साथ इमारत के गिरते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग समझ भी नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ सेकंड पहले तक जहां रौनक थी, वहां चीख-पुकार और धूल का गुबार छा गया।

स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया। अपने स्तर पर उन्होंने मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। जिला कलेक्टर पीयूष सांवरिया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल सिंघल भी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। बाद में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और अधिकारियों से जानकारी ली। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई इमारत निर्माणाधीन थी। दो मंजिल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अंदर और बाहर अभी भी काम जारी था। इसी इमारत में 'दिल्ली नॉनवेज' नाम से एक रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। शनिवार रात होने के कारण रेस्टोरेंट में अच्छी खासी भीड़ थी। हादसे के समय वहां कई ग्राहक मौजूद थे और करीब 10 से 12 लोग स्टाफ में काम कर रहे थे। अनुमान के मुताबिक, इमारत के अंदर कुल 30 से 40 लोग मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल थे। रेस्क्यू के दौरान 15 से अधिक लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। इनमें से एक छात्र समेत दो लोगों की मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी अरण्य के रूप में हुई है, जो कोटा में एलेन कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहा था। दूसरा मृतक 13 से 14 वर्ष का किशोर बताया जा रहा है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेज कोटा में भर्ती कराए गए घायलों में से एक युवक भूपेंद्र (23), जो कोटा का ही निवासी था, की भी इलाज के दौरान मौत होने की पुष्टि नर्सिंग स्टाफ ने की है। इस तरह मृतकों की संख्या को लेकर शुरुआती घंटों में अलग-अलग जानकारियां सामने आती रहीं, जिससे परिजनों और प्रशासन दोनों में भ्रम की स्थिति बनी रही।

घायलों में दो महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके नाम साजिदा और शालीन बताए गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार, कई घायलों को सिर, हाथ-पैर और रीढ़ में गंभीर चोटें आई हैं। 8 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। अस्पताल में घायलों के परिजन और परिचितों की भीड़ लगी रही, जहां हर कोई अपनों की सलामती की दुआ कर रहा था।

स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में देरी को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि हादसे के बाद क्रेन करीब डेढ़ घंटे देरी से मौके पर पहुंची, जिससे मलबा हटाने और लोगों को निकालने में बाधा आई। अगर समय पर भारी मशीनरी उपलब्ध हो जाती, तो शायद कुछ और जानें बचाई जा सकती थीं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जैसे ही सूचना मिली, सभी संबंधित एजेंसियों को मौके पर भेजा गया और पूरी सावधानी के साथ राहत-बचाव कार्य किया गया।

एक घायल छात्र ने अस्पताल में बातचीत के दौरान बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। अचानक इमारत हिलने लगी और अगले ही पल सब कुछ ढह गया। वह मलबे के नीचे दब गया था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। उसकी आंखों में अभी भी डर साफ झलक रहा था।

हादसे के बाद एहतियातन पूरे इलाके की बिजली काट दी गई, ताकि किसी और तरह का खतरा न हो। मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी तैनात रहे और भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे रहे। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पूरी होने से पहले आधिकारिक बयान देने से बच रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है।

यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि निर्माणाधीन इमारतों में व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति कैसे दी जाती है और सुरक्षा मानकों की जांच कितनी गंभीरता से होती है। कोटा जैसे शहर में, जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, इस तरह की लापरवाही कितनी जानलेवा साबित हो सकती है, यह हादसा उसकी भयावह मिसाल बन गया है। मलबे के नीचे सिर्फ लोग ही नहीं दबे, बल्कि कई परिवारों के सपने और भरोसे भी टूटकर रह गए।

शादी की रसोई से खून तक का सफर, प्रेम, विश्वासघात और हत्या की खौफनाक कहानी

श्रीगंगानगर। कभी एक शादी समारोह में खाना परोसते वेटर से शुरू हुई मामूली सी पहचान कब प्यार, फिर अवैध संबंध और आखिरकार निर्मम हत्या की साजिश में बदल गई, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में 30 जनवरी की रात हुई आशीष कुमार की हत्या अब एक सनसनीखेज लव ट्राएंगल मर्डर केस के रूप में सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस जांच में जो परतें खुलीं, वे रिश्तों, भरोसे और इंसानी लालच की ऐसी कहानी बयां करती हैं, जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठे।

पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड की साजिश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद आशीष की पत्नी अर्जु उर्फ अंजली ने रची थी। अंजली पढ़ी-लिखी थी, बीकॉम ग्रेजुएट थी और उसकी शादी 30 अक्टूबर 2025 को रावला निवासी आशीष कुमार से करवाई गई थी। आशीष एमएससी पास, शांत स्वभाव का युवक था, जिसे परिवार और समाज में एक सुलझे हुए इंसान के तौर पर जाना जाता था। शादी के बाद दोनों का जीवन सामान्य दिखता था, लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा था, जो धीरे-धीरे एक खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ रहा था।

करीब सात साल पहले अंजली की मुलाकात संजय नाम के युवक से एक शादी समारोह में हुई थी। उस समय संजय वहां वेटर का काम कर रहा था। बातचीत के दौरान दोनों के बीच पहचान बनी, नंबर भी शेयर हुए, लेकिन अंजली के पास उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था, जिससे संपर्क टूट गया। समय बीतता गया, जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन यह अधूरी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। साल 2024 में जब अंजली के पास

मोबाइल आया, तो पुराने नंबर के जरिए संजय से फिर संपर्क हो गया। बातचीत शुरू हुई, हालचाल पूछे गए और धीरे-धीरे वही पुरानी पहचान फिर से नजदीकियों में बदलने लगी। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई और यह रिश्ता प्रेम संबंध में तब्दील हो गया। इसी दौरान अंजली की शादी आशीष कुमार से तय हो गई। परिजनों की मर्जी से हुई इस शादी को अंजली ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वह दिल से इस रिश्ते में कभी रम नहीं पाई। शादी के बाद वह ससुराल रावला आ गई, जबकि उसका मायका सादुलशहर में था, जो करीब 225 किलोमीटर दूर है। यह दूरी उसके लिए सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक बोझ भी बन गई। वह अंदर ही अंदर अपने पति से दूर और संजय के और करीब होती चली गई। पुलिस के अनुसार, अंजली लगातार संजय के संपर्क में बनी रही। वैवाहिक जीवन से असंतोष और प्रेमी से लगाव ने उसके भीतर खतरनाक सोच को जन्म दिया। हत्या से करीब 16 दिन पहले वह मायके गई थी। इसी दौरान आशीष को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। अंजली और संजय की आमने-सामने मुलाकात भले ही नहीं हुई, लेकिन व्हाट्सएप कॉल के जरिए दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। हत्या वाले दिन दोनों के बीच 5 से 7 बार संपर्क होने की पुष्टि पुलिस ने की है, जिसने जांच को निर्णायक दिशा दी। 30 जनवरी की रात अंजली ने रोजमर्रा की तरह घूमने का बहाना बनाया और आशीष को घर से बाहर निकलने के लिए राजी कर लिया। पहले से तय योजना के मुताबिक उसने संजय को अपनी लोकेशन भेज दी। संजय अपने दो साथियों रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ के साथ गांव 01 केएलएम रोड पर झाड़ियों में छिपकर बैठा था। जैसे ही दंपती वहां पहुंचे, तीनों आरोपियों ने अचानक आशीष पर डंडों से हमला कर दिया। सिर और शरीर पर गंभीर वार किए गए। जब बुरी तरह घायल होने के बावजूद आशीष की सांसें चलती रहीं, तो आरोपियों ने मफलर से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद कहानी को लूट या हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक, अंजली ने अपने झुमके और आशीष का मोबाइल फोन आरोपियों को दे दिया, ताकि लगे कि किसी ने लूटपाट के दौरान हत्या की है। इसके बाद वह खुद सड़क पर गिरकर बेहोशी का नाटक करने लगी। राहगीरों ने जब यह दृश्य देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया।

शुरुआत में मामला संदिग्ध हादसा या लूट जैसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर बदल दी। रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटों और दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस का शक गहराया और जांच की दिशा बदली गई। पूछताछ के दौरान अंजली के बयानों में विरोधाभास सामने आए, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया।

एसपी अमृता दुहन ने बताया कि इस मामले में अंजली, उसके प्रेमी संजय और उसके दोनों साथियों रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों पुरुष आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है, जबकि अंजली को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान इस साजिश से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।

यह मामला न सिर्फ एक हत्या की कहानी है, बल्कि रिश्तों में पनपते अविश्वास, अधूरे प्रेम और गलत फैसलों का खतरनाक उदाहरण भी है। जिस शादी को नई जिंदगी की शुरुआत माना जाता है, वही शादी इस मामले में एक मासूम युवक के लिए मौत का कारण बन गई। श्रीगंगानगर का यह हत्याकांड अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जब भरोसा टूटता है, तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है।

सूरत में ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल उद्योग को मिला नया मंच, पहले ही प्रयास में एक्सपो बना क्षेत्रीय उद्योग की बड़ी पहचान

सूरत। दक्षिण गुजरात के औद्योगिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जुड़ गया, जब पहली बार एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिकल सेक्टर को समर्पित 'एनर्जी-पावर-इलेक्ट्रिकल एक्सपो 2026' का आयोजन किया गया और उसे उम्मीद से कहीं अधिक ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह एक्सपो 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ, जहां तीन दिनों तक उद्योग, तकनीक और नवाचार का संगम देखने को मिला।

सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुले इस एक्सपो में पहले ही दिन से विज़िटर्स की भारी आवाजाही शुरू हो गई थी। चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि "पावरिंग द फ्यूचर – टुडे" थीम के साथ आयोजित इस एक्सपो का उद्देश्य एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिकल सेक्टर के समग्र विकास को गति देना था। उन्होंने कहा कि यह चैंबर की ओर से इस सेक्टर में पहली पहल थी, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ट्रेडर्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स ने उत्साह दिखाया, उससे साफ है कि इस तरह के स्पेशलाइज़्ड प्लेटफॉर्म की इंडस्ट्री को लंबे समय से आवश्यकता थी।

इस एक्सपो में सूरत के साथ-साथ अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर, पुणे, मुंबई और ग़ाज़ियाबाद जैसे प्रमुख औद्योगिक शहरों से कुल 60 एग्ज़िबिटर्स ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े थे, जबकि शेष ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित थे। प्रदर्शनी में रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स, सपोर्टिंग सर्विसेज़, सॉल्यूशंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स और तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जिसने विज़िटर्स को खासा आकर्षित किया।

निखिल मद्रासी के अनुसार, राज्य और देशभर में रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन सॉल्यूशंस की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में यह एक्सपो केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान, तकनीकी जानकारी और भविष्य की साझेदारियों का सशक्त मंच बनकर उभरा। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत में पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों और ऊर्जा दक्ष समाधानों के प्रति बढ़ती रुचि दक्षिण गुजरात के औद्योगिक विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

तीन दिनों तक चले इस आयोजन में इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोजेक्ट डेवलपर्स और टेक्निकल स्टूडेंट्स सहित विभिन्न वर्गों के 12,000 से अधिक विज़िटर्स ने एक्सपो का दौरा किया। बड़ी संख्या में आए विज़िटर्स ने न केवल प्रदर्शित उत्पादों और सेवाओं की जानकारी ली, बल्कि एग्ज़िबिटर्स के साथ गहन चर्चा भी की। कई एग्ज़िबिटर्स ने बताया कि उन्हें मौके पर ही ठोस बिज़नेस इन्क्वायरीज़ मिलीं और भविष्य की डील्स को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई, जिससे इस एक्सपो की व्यावसायिक उपयोगिता भी सिद्ध हुई।

एक्सपो का माहौल पूरी तरह प्रोफेशनल और ऊर्जा से भरपूर रहा। स्टॉल्स पर नई-नई तकनीकों, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़े प्रोडक्ट्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सेक्टर आने वाले वर्षों में औद्योगिक विकास की रीढ़ बनने जा रहा है। सूरत और दक्षिण गुजरात जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यह एक्सपो एक ऐसा मंच साबित हुआ, जहां लोकल इंडस्ट्री को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से जुड़ने का अवसर मिला।

कुल मिलाकर, 'एनर्जी-पावर-इलेक्ट्रिकल एक्सपो 2026' ने यह साबित कर दिया कि सूरत केवल टेक्सटाइल और डायमंड तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल सेक्टर में भी वह एक मजबूत पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले ही प्रयास में मिली शानदार सफलता ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में इस एक्सपो को और व्यापक रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिससे न केवल उद्योग को लाभ होगा, बल्कि दक्षिण गुजरात के औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

महिलाओं के हृदय स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर केंद्रित चैंबर का विशेष सत्र, जागरूकता और संवाद पर रहा जोर

सूरत। तेजी से बदलती जीवनशैली, बढ़ता तनाव, काम और परिवार के दोहरे दायित्वों के बीच महिलाओं का स्वास्थ्य आज एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है। विशेष रूप से हृदय संबंधी रोग और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं अब केवल उम्र तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि कम आयु की महिलाओं को भी प्रभावित करने लगी हैं। इसी पृष्ठभूमि में द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) द्वारा अपनी निरंतर हेल्थ सीरीज के अंतर्गत "हेल्दी हार्ट और महिलाओं की वेलनेस" विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसने महिलाओं को न केवल जानकारी दी बल्कि आत्ममंथन और संवाद का अवसर भी प्रदान किया।

नानपुरा स्थित समृद्धि भवन में आयोजित इस सत्र में सुबह से ही उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। महिला उद्यमी, चैंबर सदस्य, कामकाजी महिलाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सत्र का उद्देश्य केवल चिकित्सकीय जानकारी देना नहीं था, बल्कि महिलाओं को यह एहसास कराना था कि अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लेना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चैंबर के मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इस दौड़ में वे अक्सर अपनी सेहत को पीछे छोड़ देती हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती है। उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए भी यह जरूरी है कि वे स्वयं के साथ-साथ अपने कर्मचारियों और परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें। चैंबर की हेल्थ सीरीज इसी सोच का विस्तार है, जिसका उद्देश्य बीमारी के बाद इलाज नहीं, बल्कि बीमारी से पहले जागरूकता है।

सत्र के मुख्य वक्ता आईवीएफ और इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉ. रवींद्र कोराट ने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अनेक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज की महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन, फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं, पीसीओडी, थायरॉइड और मातृ स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि कैसे असंतुलित खानपान, नींद की कमी और मानसिक तनाव शरीर के भीतर धीरे-धीरे गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं।

डॉ. कोराट ने विशेष रूप से महिलाओं में हृदय रोग के लक्षणों पर ध्यान दिलाया और कहा कि महिलाओं में हार्ट अटैक के संकेत अक्सर पुरुषों से अलग होते हैं, जिसके कारण समय पर पहचान नहीं हो पाती। थकान, घबराहट, सांस लेने में परेशानी, पीठ या जबड़े में दर्द जैसे संकेतों को अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये गंभीर चेतावनी हो सकते हैं। उन्होंने नियमित हेल्थ चेक-अप, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच को अनिवार्य बताते हुए कहा कि समय रहते सतर्कता कई जिंदगियां बचा सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि हृदय स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और मानसिक संतुलन इसमें अहम भूमिका निभाता है। योग, प्राणायाम, हल्का व्यायाम, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बनाकर महिलाएं न केवल बीमारियों से बच सकती हैं, बल्कि एक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी जीवन भी जी सकती हैं। उनके संबोधन के दौरान महिलाओं ने खुलकर प्रश्न पूछे और अपनी व्यक्तिगत समस्याएं साझा कीं, जिनका समाधान विशेषज्ञ द्वारा सहज और संवेदनशील तरीके से किया गया।

कार्यक्रम की सामाजिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए चैंबर की इंडस्ट्रियल वर्कर्स हेल्थ कमेटी के चेयरमैन डॉ. जगदीश वघासिया ने कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि चैंबर भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्र का संचालन को-चेयरमैन निखिल वघासिया ने कुशलता से किया, जिससे पूरा कार्यक्रम संवादात्मक और रोचक बना रहा।

कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित महिलाओं ने इस सत्र को अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायी बताया। कई प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह के मंच न केवल जानकारी देते हैं, बल्कि महिलाओं को अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का आत्मविश्वास भी देते हैं। कुल मिलाकर, यह जागरूकता सत्र महिलाओं के हृदय स्वास्थ्य और समग्र कल्याण की दिशा में एक सार्थक और दूरगामी पहल के रूप में सामने आया, जिसने यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत जागरूकता और सही निर्णयों से होती है।

पाली में हवाई जहाज नुमा ड्रोन गिरा, ग्रामीणों में मची अफरा-तफरी; जांच में तकनीकी खराबी का खुलासा

पाली। राजस्थान के पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अप्रत्याशित घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। अरटिया गांव के पास आसमान से अचानक एक हवाई जहाज नुमा ड्रोन गिर गया, जिसे देखकर ग्रामीणों की सांसे ठहर गईं और पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद स्थिति की गंभीरता का पता चला और जांच में तकनीकी खराबी सामने आई।

जानकारी के अनुसार, यह ड्रोन कॉरिडोर सर्वे के लिए उड़ाया गया था। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह नियंत्रण से बाहर हो गया और अरटिया गांव की सरहद में आ गिरा। ड्रोन गिरने के साथ ही ग्रामीणों में शोर और चिंता फैल गई। कई लोगों ने इसे देखते ही इसे खतरे के रूप में लिया और अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर तनाव महसूस किया। इस बीच घटना की सूचना रोहट थाना पुलिस तक पहुंची, जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि किसी प्रकार का खतरा नहीं है। स्थानीय पुलिस ने ड्रोन गिरने के कारणों की जांच के लिए कॉरिडोर सर्वे में लगे कंपनी के कर्मचारियों को मौके पर बुलाया। शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ कि ड्रोन पूरी तरह तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित होकर गिरा और इसका किसी भी तरह से सुरक्षा या जनहानि से कोई संबंध नहीं था। ड्रोन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह जमीन पर टूटा पड़ा दिख रहा है।

विशेष रूप से यह घटना उस समय सुर्खियों में आई जब ग्रामीण इसे हवाई जहाज जैसी आकृति के कारण पहले खतरनाक समझ बैठे थे। गांव वालों की घबराहट की वजह यह भी थी कि हाल ही में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ड्रोन को लेकर अफवाहें फैल चुकी हैं और भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल लगातार देखा गया है। ग्रामीणों ने प्रारंभ में इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए काफी चिंता जताई, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद उन्होंने चैन की सांस ली।

इस घटना ने यह भी उजागर किया कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद लोगों में अभी भी ड्रोन जैसी नई तकनीकी वस्तुओं को लेकर जागरूकता की कमी है और उन्हें सुरक्षा को लेकर आशंका रहती है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि अगर भविष्य में ऐसी तकनीकी वस्तुएं गिरें या अनियंत्रित हों तो तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अफवाह या पैनिक स्थिति से बचा जा सके।

सांबा सीमा पर सतर्कता की जीत, बीएसएफ ने घुसपैठ की साजिश नाकाम की

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में भारत–पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर सीमा सुरक्षा बल की मुस्तैदी देखने को मिली है। रविवार शाम रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। यह घटना बॉर्डर आउटपोस्ट बल्लर के पास शाम करीब सात बजे सामने आई, जब जवानों को सीमा पर संदिग्ध गतिविधि नजर आई और उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाल लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीमा पर नियमित गश्त और निगरानी के दौरान बीएसएफ जवानों ने एक व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते हुए आगे बढ़ते देखा। चुनौती दिए जाने पर उसकी गतिविधियां और भी संदिग्ध लगीं, जिसके बाद जवानों ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि पकड़ा गया व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक है, जो अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां उससे सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं।

सूत्रों का कहना है कि पूछताछ का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि घुसपैठिए का भारत में आने का मकसद क्या था, वह किसी आतंकी या तस्करी नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं, और सीमा पार से उसे किस तरह की मदद मिल रही थी। सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि क्या यह घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या फिर अकेले की गई घुसपैठ की कोशिश। फिलहाल उससे बरामद सामान और दस्तावेजों की भी गहनता से जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि सांबा सेक्टर लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की दृष्टि में संवेदनशील माना जाता रहा है। अतीत में भी इस क्षेत्र से घुसपैठ, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिशें सामने आती रही हैं। हालिया घटना ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों को उजागर किया है। इससे पहले 26 जनवरी को भी इसी जिले में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था, जिसकी पहचान लाहौर निवासी मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई थी। उस घटना के बाद से ही सीमा पर निगरानी और सख्त कर दी गई थी।

हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बढ़ी हलचल और बार-बार सामने आ रही घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए बीएसएफ ने तकनीकी निगरानी, अतिरिक्त जवानों की तैनाती और गश्त को और मजबूत किया है। ड्रोन गतिविधियों, संदिग्ध मूवमेंट और सीमा के नजदीकी इलाकों में चौकसी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बीएसएफ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सीमा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

इस ताजा गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियां एक अहम सफलता के रूप में देख रही हैं, क्योंकि समय रहते घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय भी इस कार्रवाई में अहम साबित हुआ। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पकड़े गए व्यक्ति का उद्देश्य क्या था, लेकिन फिलहाल इस घटना ने यह संदेश जरूर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की नजरें चौकस हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जा रही है।

जापान की राजनीति में नया अध्याय, सनाए ताकाइची के नेतृत्व में एलडीपी को ऐतिहासिक जनादेश

टोक्यो/नई दिल्ली। जापान की राजनीति में एक नया और निर्णायक अध्याय उस समय लिखा गया, जब प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज कर ली। चुनाव परिणामों ने न केवल सत्ता संतुलन को पूरी तरह एलडीपी के पक्ष में मोड़ दिया, बल्कि जापान के लोकतांत्रिक इतिहास में इसे एक रिकॉर्ड जीत के रूप में दर्ज करा दिया। मतदान समाप्त होने के महज दो घंटे के भीतर ही ताकाइची के गठबंधन ने बहुमत के लिए आवश्यक 233 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जनता ने इस बार बेहद मजबूत और स्पष्ट जनादेश दिया है। अब तक आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 465 सदस्यीय सदन में एलडीपी को 312 सीटें मिली हैं और कई सीटों पर मतगणना के अंतिम चरण में भी पार्टी बढ़त बनाए हुए है।

इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सनाए ताकाइची की राजनीतिक स्थिति और अधिक मजबूत हो गई है। अक्टूबर में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से ही उन्हें लेकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्सुकता बनी हुई थी। शुरुआती दौर में जहां कुछ विश्लेषकों ने उनकी नेतृत्व क्षमता और पार्टी के भीतर संतुलन साधने की चुनौती पर सवाल उठाए थे, वहीं समय के साथ उनकी छवि एक निर्णायक और स्पष्ट सोच वाली नेता के रूप में उभरी। चुनावी नतीजों ने यह साबित कर दिया कि ताकाइची न केवल अपनी पार्टी को एकजुट रखने में सफल रहीं, बल्कि आम मतदाताओं के बीच भी भरोसा कायम कर पाईं।

चुनावी अभियान के दौरान ताकाइची ने आर्थिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक मंच पर जापान की भूमिका को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि बदलते वैश्विक हालात में जापान को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ सुरक्षा चुनौतियों का भी मजबूती से सामना कर सके। विश्लेषकों का मानना है कि उनका यही स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा रुख मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रहा। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में उनकी वह भावुक अपील भी निर्णायक साबित हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो वह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगी। इस बयान ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया और मतदाताओं ने उन्हें अभूतपूर्व समर्थन देकर सत्ता की कमान मजबूती से सौंप दी।

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिलने लगीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जीत की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि सनाए ताकाइची के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें बधाई देते हुए जापान-अमेरिका गठबंधन को और सुदृढ़ करने की उम्मीद जताई। इन संदेशों से साफ है कि ताकाइची की जीत को केवल घरेलू राजनीति की सफलता नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस भारी बहुमत के बाद ताकाइची के सामने अवसरों के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी होंगी। जापान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से सुस्ती, महंगाई और जनसंख्या में गिरावट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। इसके अलावा चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और पूर्वी एशिया में बदलते सामरिक समीकरण भी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकते हैं। ताकाइची पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि वह अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन को और मजबूत करने तथा रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएंगी। युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि वह भविष्य की चुनौतियों को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण रखती हैं।

इस ऐतिहासिक जनादेश के साथ जापान की राजनीति में स्थिरता की उम्मीद भी बढ़ी है। मजबूत बहुमत से लैस सरकार के पास अब नीतिगत फैसले लेने और सुधारों को लागू करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक ताकत है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ताकाइची सरकार आर्थिक सुधार, तकनीकी नवाचार और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में आक्रामक पहल कर सकती है। कुल मिलाकर, यह चुनाव परिणाम न केवल सनाए ताकाइची के नेतृत्व पर जनता की मुहर है, बल्कि जापान के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक मोड़ भी माना जा रहा है।

भावनगर मंडल के अंतर्गत चलने वाली तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए भावनगर मंडल से होकर चलने वाली तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित किए गए हैं। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन ट्रेनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09018 वेरावल – बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 30 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09017 बांद्रा टर्मिनस – वेरावल साप्ताहिक स्पेशल को 29 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

2. ट्रेन संख्या 09208 भावनगर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 26 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09207 बान्द्रा टर्मिनस – भावनगर टर्मिनस को 27 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09216 भावनगर – गांधीग्राम दैनिक अनारक्षित स्पेशल को 31 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम –भावनगर टर्मिनस दैनिक अनारक्षित स्पेशल को भी 31 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

उपर्युक्त सभी आरक्षित ट्रेनों के विस्तारित फेरों की बुकिंग 08 फरवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। ट्रेनों के ठहराव के समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर मंडल के सिहोर जं. पर साहसिक कार्य: प्वाइंट्समैन ने चलती ट्रेन से गिरती युवती की बचाई जान

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के अंतर्गत सिहोर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 08 फरवरी, 2026 (रविवार) की सुबह सतर्कता और साहस की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। चलती ट्रेन संख्या 59229 बोटाद–भावनगर दैनिक पैसेंजर से उतरने के दौरान संतुलन खोकर गिर रही एक युवती की जान स्टेशन पर तैनात सतर्क प्वाइंट्समैन ने अपनी तत्परता से बचा ली।

यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि युवती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने वाली थी, लेकिन प्वाइंट्समैन ने बिना एक पल गंवाए तुरंत दौड़कर उसे खींच लिया और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर ले आए। इस फुर्तीले और साहसिक बचाव कार्य की चारों ओर सराहना की जा रही है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि युवती चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रही थी, इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। मौके पर उपस्थित प्वाइंट्समैन श्री राज कुमार ने अपनी सतर्कता, फुर्ती और सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल कार्रवाई की, जिससे एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। इस घटना को ट्रेन में सवार यात्रियों एवं प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने स्तब्ध होकर देखा।

यह घटना चलती ट्रेनों में चढ़ने या उतरने के दौरान होने वाले खतरों को रेखांकित करती है। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर दुर्घटनाएं इसी प्रकार की लापरवाही के कारण होती हैं, जब यात्री ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले उतरने या चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं। कई बार भारी सामान के साथ चढ़ने-उतरने से संतुलन बिगड़ जाता है और गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें। ट्रेन के पूरी तरह रुकने के बाद ही सुरक्षित रूप से चढ़ें अथवा उतरें तथा रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें।